शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री राजू धिंगान

दिनांक : 20.03.2018

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या : 30

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	पिछले 5 वर्षों में शहर को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, तय किए गए लक्ष्य के अनुपात में कितने शौचालयों का निर्माण किया गया है;	**दिल्ली छावनी परिषद** पिछले 5 वर्षों में शहर को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, अभियांत्रिकी विभाग द्वारा एक शौचालय (छः सीट तीन पुरूष और तीन महिला) का निर्माण किया गया है । **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्** पिछले 5 वर्षों में नई दिल्ली नगर निगम पालिका ने अपने क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु 87 नये शौचालयों का निर्माण व 29 शौचालयों का नवीनीकरण कार्य पुर्ण किया है । इस प्रकार अभी तक नई दिल्ली नगर निगम पालिका ने 304 सार्वजनिक शौचालयों व 38 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पुर्ण कर स्वच्छ भारत मिशन द्वारा जारी निर्देशानुसार सार्वजनिक शौचालय एक कि.मी. की दूरी पर व सामुदायिक शौचालय जे.जे.कैम्प से 500 मीटर की दूरी का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है एवं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् को पहले ही खुले में शौच से मुक्त क्षेत्र भी घोषित किया जा चुका है । **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड** दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के द्वारा 'स्वच्छ भारत मिशन' के अन्तर्गत 29 स्थानों पर 1312 टॉयलेट सीट का निर्माण का कार्य शुरू किया गया। इनमें से 23 स्थानों पर 914 टॉयलेट सीटों का कार्य पूरा कर लिया गया है। अनय 5 स्थानों पर 338 टॉयलेट सीटों का कार्य 30–4–2018 तक कर लिया जायेगा । एक परियोजना (60 सीट) जनता के प्रतिरोध एवं आर्किटेक्चरल ड्राईंग की उपलब्धता में देरी के कारण 30–06–2018 तक पूरा करने की सम्भावना है । **शहरी विकास विभाग (स्वच्छ भारत मिशन)** शहरी निकायों ने सामुदायिक/ सार्वजानिक/ व्यक्तिगत शौचालयों के लिए एस.बी.एम. के अन्तर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये हैं । किन्तु निर्धारित एस.बी.एम. मानदण्डों के तहत शौचालयों का निर्माण करके सभी निकायों ने अपने क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया है। तीनों नगर निगमों ने स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत लगभग 450 व्यक्तिगत शौचालयों (IHHT) का निर्माण हुआ है । दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने स्व. भा.मि. में 1312 सामुदायिक शौचालयों का लक्ष्य निर्धारित किया है। उसमें से 914 बनकर तैयार हैं । **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** पिछले 5 वर्षों में शहर को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत, किसी भी शौचालय का निर्माण नही हुआ है । वर्ष 2017–18 में स्वच्छ भारत मिशन में 92 शौचालयों के निर्माण लक्ष्य रखा गया है तथा इसका निर्माण अभियान्त्रिक विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा इसके लिए आवश्यक धन राशि उपलब्ध करा दी गई है । **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** पिछले 5 वर्षों में शहर को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत, तय किये गये लक्ष्य के अनुपात में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में शतप्रति लक्ष्य को प्राप्त किया । **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा 130 शौचालयों (623 सीट) का निर्माण किया गया एवं 51 शौचालयों (153 सीट) का निर्माण किया जाना है ।
ख	पिछले 5 वर्षों में किन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हुई;	**दिल्ली छावनी परिषद** जी हॉ, पिछले 5 वर्षों में मोबाईल टॉयलेट लगाने में देरी हुई । **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्** निर्धारित शौचालयों के निर्माण से सम्बन्धित कियान्वयन में कोई देरी नहीं हुई अपितु पुराने बने हुए शौचालयों के नविनिकरण के कार्य में जन हितार्थ को ध्यान में रखकर ही कार्य पूरा किया जा रहा है । **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड** उपरोक्तानुसार जैसा (क) के उत्तर में उल्लेखित है। **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** वर्ष 2017 तक बजट न मिलने के कारण देरी हुई । **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** पिछले 5 वर्षों में किसी भी परियोजना के कार्यान्वयन में देरी नहीं हुई । **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** शौचालयों का निर्माण स्थान की उपलब्धता के अनुसार किया जा रहा है ।
ग	उस देरी के क्या कारण हैं;	**दिल्ली छावनी परिषद** उपरोक्त के अनुसार रक्षा भूमि पर अतिकमण होने के कारण मोबाईल टॉयलेट लगाने में देरी हुई

		। **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्** उपरोक्तानुसार **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड** उपरोक्तानुसार जैसा (क) के उत्तर में उल्लेखित है। **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** वर्ष 2017 तक बजट न मिलने के कारण देरी हुई । **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** उपरोक्तानुसार **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** उपरोक्तानुसार
घ	कितनी टॉयलेट सीटस चालू हालत में है और कितने लोगों द्वारा उनका इस्तेमाल किया जा रहा है; और	**दिल्ली छावनी परिषद** 498 टॉयलेट सीट चालू हालत में है और लगभग 8000 लोगों के द्वारा टॉयलेट इस्तेमाल किये जाते हैं । **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्** सभी 1340 टॉयलेट सीट्स व 845 मूत्रालय पात्र चालू हालत में हैं जिनका उपयोग अनुमानित ढाई से तीन लाख स्थाई निवासियों व 15 लाख अस्थाई निवाशियों के द्वारा किया रहा है । **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड** सभी 914 टॉयलेट सीटर जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं । लगभग 30000 लोगों द्वारा इन टॉयलेट सीटों का इस्तेमाल किया जा रहा है । **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 300 सी.टी. सी. चालू हालत में जिसमें 3206 सीटें पुरूषों के लिए तथा 2526 सीटें महिलाओं के लिए हैं इसके अतिरिक्त 68 Public Toilet है । इन सीटों आम जनता द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है । **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** वर्तमान में लगभग 14500 सीट्स चालू हालत में हैं । **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** सभी सीट्स चालू हालत में हैं एवं उनका उपयोग नागरिकों द्वारा किया जा रहा है ।
ड	क्या विभाग द्वारा नागरिकों को खुले में शौच करना बंद कर इन शौचालयों का इस्तेमाल करने के संबंध में जागरूक करने हेतु कोई अभियान चलाया गया ह?	**दिल्ली छावनी परिषद्** दिल्ली छावनी परिषद द्वारा खुले शौच की प्रथा को बन्द करने के लिए तथा उपरोक्त शौचालय को इस्तेमाल करने के संबंध में समय–समय पर अभियान चलाये गये हैं, जिसके अंश निम्न प्रकार से हैं:– 1 जनसम्बोधन के माध्म से बार–बार घोषणाए की गई । 2 प्रभावित क्षेत्र में बैनर लगाए गये हैं । 3 पूरे छावनी क्षेत्र में हैंडबिल्स और पोस्टर लगाए गये हैं । 4 खुले में शौच को रोकने के लिए व उनको शौचालय के प्रयोग करने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिला ए.एस.आई. सहित ए.एस.आई. के पर्यवेक्षण में समर्पित टीम को काम पर लगाया गया था । 5 स्कूली बच्चों द्वारा प्रभावित क्षेत्र में थीम आधारित प्ले का आयोजन किया गया था । 6 प्रभावित क्षेत्रों में छावनी सार्वजनिक अस्पताल, दिल्ली छावनी परिषद के डॉक्टरों द्वारा व्याख्यान दिया गया, प्रभावित क्षेत्र के निवासियों को खुले में शौच के नुकसान तथा शौचालयों के प्रयोग के लाभ बताये गये । **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्** समय–समय पर पट विज्ञापन व बैनर लगा कर लोगों को खूले में शौच न करने व शौचालय उपयोग करने के सन्दर्भ में जागरूक अभियान चलाया जाता है । **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड** हॉ, गैर सरकारी संगठनो के सहयोग से 'स्वच्छता ही सेवा' के नाम 15–9–2017 से 2–10–2017 तक जे.जे. बस्तियों में लोगों को जागरूक करने के लिये अभियान चलाया गया था। **शहरी विकास विभाग (स्वच्छ भारत मिशन)** वर्तमान में 5 शहरी निकायों में से नई दिल्ली पालिका परिषद् एवं दिल्ली छावनी परिषद् को शहरी विकास एवं आवासन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा खुले में शौच मुक्त क्षेत्र सत्यापित किया है । तीनों नगर निगमों ने भी अपने क्षेत्र को शौच मुक्त घोषित कर दिया है । उनका सत्यापन कार्य प्रगति में है । शहरी निकाय समय–समय पर खुले में शौच मुक्त हेतु जागरूकता अभियान चला रहे हैं । **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** जी हां, इस के लिए रोको–टोको तथा सीटी बजाओ अभियान सभी क्षेत्रों में चला कर तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा लोगों को जागृत किया गया है । **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम नुक्कड नाटक, पोस्टर्स, एफ. एम. चैनल, सीटी बजाओं अभियान, रोको–टोको अभियान चला कर आम नागरिकों को खुले में शौच न करने के लिए एवं शौचालयों के इस्तेमाल करने के लिए जागरूक हेतु अभियान चलाए गए हैं। **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** जी हां, जागरूक करने हेतु अभियान चलाएं गये हैं ।

H.S. Parmar
Dy. Secy. (Urban Development)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat

विधानसभा तारांकित प्र० सं०- 30, श्री- राजू धिंगान, विधायक द्वारा पूछे गये प्रश्नो हेतु पूरक सामग्री :-

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शहरी विकास एवं आवसन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शौचालयो के निर्माण हेतु निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गये थे :-

1. व्यक्तिगत शौचालय (IHHT) – 125398
2. सार्वजनिक शौचालय (PublicT) - 9156
3. सामुदायिक शौचालय (communityT) - 1982

मिशन लागू होने के प्रथम दो वर्षो तक सभी शहरी निकाय अपने क्षेत्र मे व्यक्तिगत शौचालयों (IHHT) की आवश्यकता शून्य बताते रहे थे। तदुपरान्त, State High Powered Committee (SHPC) के अनुमोदन एवं मा० मंत्री, श० वि० विभाग की अनुसंशा पर राज्य कोष की धनराशि ₹ 1333/- से बढ़ाकर ₹ 4000/- प्रति व्यक्तिगत शौचालयो हेतु प्रावधान किया गया है। व्यक्तिगत शौचालयो हेतु अभी तक जो आवे-दन नगर निगमो को प्राप्त हुए है उसमे से लगभग 450 बनकर तैयार है।

तीनो नगर निगमो को खुले मे शौच मुक्त करने मे DUSIB ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। स्वच्छभारत के अन्तर्गत 812 सामुदायिक शौचालयो की सीट के अलावा अन्य परियोजनाओ से लगभग 19000 सीटो का निर्माण हुआ है।

(हस्ताक्षर)

उपसचिव (स्व०भा०)